SHRI RAM NAIK: Sir, nowhere there is a proposal for supplying LPG through pipeline within a particular city, bui we are bringing LPG gas through the longest pipeline in the world, covering 1400 KMs, from Gujarat to Delhi. So, LPG is brought....*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: *Via* Rajasthan.

SHRI RAM NAIK: Yes, Sir, *via* Rajasthan, *via* Madhya Pradesh, *via* Haryana to Delhi. But the point is that we are trying to see if we can devolve a system like that. But at present only some cities in a particular housing complex, if they take on wholesale basis, then, they supply through their retail price. That type of experiment is going on, but no decision has been taken so far.

नेपाल से बहने वाली नदियों पर बांध

*282. **प्रो.राम देव भंडरी**: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क्) नेपाल से उद् भूत और बिहार से होकर बहने वाली नदियों पर बांध बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच चल रही वार्ता में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है :,

(ख)क्या इस वार्ता में बिहार सरकार के प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है :, और

(ग) बिहार में इन नदियों से होने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती चक्रवर्ती): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क्) भारत और नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जुलाई-अगस्त, 2000 के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसरण में नेपाल से निकलने वाली नदियों में बाढ़ नियन्त्रण के लिए भंडारण स्कीमों अर्थात कोसी नदी पर सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना और सनकोसी भंडारण व व्यपवर्तन स्कीम, कमला नदी पर कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना और बगमती नदी पर बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना सहित भारत और नेपाल के बीच जल संसाधनों सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जल संसाधनों संबंधी भारत-नेपाल संयुक्त समिति का गठन किया गया था।

सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सुनकोसी भंडारण व डाइवर्जन स्कीम के संबंध में भारत-नेपाल संयुक्त विशेषज्ञ दल पहले ही सहमत हो चुके है और इस परियोजना की एक प्रारम्भिक रिपोट्र को अंतिम रूप दिया जा चुका है जो कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त अध्ययन दल के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज का कार्य करेगी । इस परियोजना के लिए संयुक्त क्षेत्र अन्वेषण/ अध्ययन शुरू करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ।

नेपाल में चीसापानी के निकट कमला नदी और नूनथर के निकट बागमती नदी पर बहुउद्देश्यीय भंडारण बांधों के निर्माण के लिए प्रस्ताव पर नेपाल के साथ विचार-विमर्श चल रहा है ।इस संबंध में सहमति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं हालांकि नेपाल का यह मानना है कि सामाजिक और पर्यावरणी या बाधाओं के कारण ये परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं होगी ।

(ख) जीं हो । विशेषज्ञों के संयुक्त दल में राज्य सरकार का प्रतिनिधि इंजीनियर-इन-चीफ (जल संसाधन विकास), बिहार सरकार कर रहे हैं ।

(ग) बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और प्रचालन का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है । केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है ।

जल संसाधन मंत्रालय के तहत गगां बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने गंगा बेसिन में बाढ़ लाने वाली सभी नदियों के लिए बाढ़ प्रबंधन के संबंध में विस्तृत योजनाएं तैयार की है तथा इनमें दी गई सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए इन्हें बिहार सहित राज्य सरकारों को भेजा है । इसके अतिरिक्त, बाढ़ की समस्या के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने भी अनेक समितियों/ विशेषज्ञ दलों का गठन किया है जिनकी सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए बिहार सहित राज्य सरकारों को भेजा गया है ।

केन्द्र सरकार भी गंभीर कटाव-रोधी स्कीमों, नदियों के तटबधों को ऊचां उठाने और सुदृढ़ करने तथा विस्तार करने और ऊचें किए गए प्लेटफामौं और जलनिकास चैनलों जैसे बाढ़ रोधी कार्यक्रमों के तहत कार्य शुरू करने के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मुहैया करती रही है । इसके अतिरिक्त, बाढ़ से होने वाले विनाश की पूर्व चेतावनी प्रणाली “नामक एक योजना स्कीम भी वर्ष 1989 से प्रचालनाधीन है ।

Dam on river flowing from Nepal

†*282. PROF. RAM DEO BHANDARY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the details of the progress made in the discussion between India and Nelpal for constructing dams over rivers passing through Bihar and originating from Nepal;

(b) whether representative of Bihar Government is included in the discussion; and

(c) the steps being taken by Government to solve the problem of the floods in Bihar due to these rivers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In pursuance to the decision taken by the Hon'ble Prime Minister of Nepal and India during July-August, 2000, the India-Nepal Joint Committee on Water Resources (JCWR) was set up to discuss all important issues between India and Nepal on water resources including storage schemes to control floods in rivers flowing from Nepal namely, Sapta Kosi High Dam Multipurpose Project & Sun Kosi Storage cum Diversion Scheme on river Kosi, Kamla Multipurpose Project on river Kamla and Bagmati Multipurpose Project on river Bagmati.

In respect of Sapta Kosi High Dam Multipurpose Project & Sun Kosi Storage cum Diversion Scheme, the Joint Team of Experts (JTE) of India-Nepal has already come to an understanding and an Inception Report of this project has been finalised to be a guiding document for the Joint Study Team for preparation of the Detailed Project Report (DPR). The Government of India has already approved the proposal for setting up of a Joint Project Office to take up the Joint field investigation/studies and preparation of DPR for the Project.

Proposal for construction of Multipurpose Storage dams on river Kamla near Chisapani and on river Bagmati near Noonthar in Nepal

† Original notice of the question was received in Hindi.

are under discussion with Nepal. Efforts to work out an understanding in this regard are in progress though Nepalese feel that these projects may not be feasible because of social and environmental implications.

(b) Yes, Sir. The Engineer-in-Chief (Water Resources Department), Government of Bihar is representing the State Government in the Joint Team of Experts.

(c) Flood Management being a State subject, the responsibility of planning, funding, executing and operating flood control schemes rests with the concerned State Government. The assistance rendered by the Central Government is technical, catalytic and promotional in nature.

Ganga Flood Control Commission under the Ministry of Water Resources has prepared comprehensive plans for flood management for all the rivers causing floods in the Ganga basin and sent the same to the State Governments including Bihar for implementation of the recommendation made therein. In addition, the Government of India has also set up a number of Committees/Expert Groups to study the problem of floods, the recommendations of which have been sent to the State Governments including Bihar for implementation.

The Central Government has also been providing financial assistance to the State Government through various Centrally Sponsored Scheme to take up the works under critical anti-erosion schemes, raising & strengthening and extension of embankments along the rivers; and flood proofing programme such as construction of raised platforms and drainage channels. In addition, as a non-structural measure to forewarn and manage flood disasters, a plan scheme namely, "Flood Forecasting & Warning system on rivers common to India & Nepal" has also been in operation since 1989.

प्रो.राम देव भंडारी: आदरणीय सभापति जी, मंत्री जी ने काफी लंबा-चौड़ा जवाब दिया है मगर इस जवाब में कुछ भी सार्थक नहीं है । कहा जा सकता है कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया " । मान्यवर....

श्री सभापति: आप जल्दी क्वेश्चन के रूप में पूछिए ताकि ये बता सकें ।

प्रो.राम देव भंडारी : महोदय,मैं आपको भी कुछ जानकारी देना चाहता हूं...

श्री सभापति: नहीं, जानकारी नहीं देनी है । आप जानकारी इनसे लीजिए ।

प्रो. राम देव भंडारी: वैसी आपको जानकारी होगी, आप बहुत ही अनुभवी राजनेता है । आपको

देश के सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी होगी। महोदय, यह जो समस्या हैं , यह जो सवाल है जिसके साथ न सिर्फ बिहार का विकास, बल्कि बिहार की तकदीर भी जुड़ी हुई है । नेपाल से जो बड़ी-बड़ी नदियां आती है, हर साल बिहार के 20-22 जिलों को तबाह करती है करोड़ों का नुकसान होता है, जान-माल की क्षति होती है । लगातार हम लोग इस सदन में और दूसरे सदन में भी बाढ़ की इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार से निवेद करते रहते है, सरकार का दबाव डालते रहते है मगर हर बार"ढाक के वही तीन पात" होते है ।महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि जुलाइ – अगस्त,2000 में भारत और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्रियों के बीच-वार्ता हुई। उस वार्ता में नेपाल से निकलने वाली निदयां में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी नदी पर सप्त कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना, कमला नदी पर कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना, बागमती नदी पर बागमती बहुउद्देश्यी परियोजना की बात थी। कमला नदी मेरे गांव से होकर जाती है। मैं भुक्तभोगी हूं। हर वर्ष जब उसमें बाढ़ आती है तो उसका तटबधं टूटता है। मेरे घर से नदी की दूसरी ओर एक गांव है, इस बार तो पूरा गांव ही बह गया। माननीय लालू जी उस गांव मे, उस बांध पर गए थे। यह समस्या कोई एक गांव की नहीं है। कमला नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे, बागमती नदी के किनारे दर्जनों ऐसे गाव है जिन्हें हर वर्ष यह दुख सहना पड़ता है, यह विभीषिका सहनी पड़ती है । 2000 में प्रधानमंत्रियों के बीच जो बात हुई थी उसमें भारत-नेपाल संयुक्त समिति का गठन किया गया था प्रारंभिक रिपोट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसमें तीन नदियों पर बांध बनाने की बात थी। उन्होने लिखा है कि-सप्तकोसी उच्च बाध बहुउद्देश्यीय परियोजना की प्रारंभिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है । यह भी लिखा है कि सुयंक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ कमला नदी पर भी बहुउद्देश्यी बांध बनाने की योजना थी...**(व्यवधान)**....

श्री सभापति: आप पूछ लीजिए कि क्या कमला नदी पर बांध बनाने की योजना है ?

प्रो.राम देव भंडारी: मंत्री जी जितना लंबा-चौड़ा जवाब दिया है , उतना लंबा-चौड़ा सवाल मैं नहीं पूछना चाहता हूं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: : नहीं, नहीं पूछिए। आप पूछ सकते हैं।

प्रो.राम देव भंडारी: मुझे थोड़ा सा तो समय दीजिए । आपने काफी लंबा-चौड़ा जवाब दिया है।

श्री सभापति: आप केवल कमला नदी के बारे में पूछ लीजिए, बाकी प्रोजेक्ट तो मंजूर कर ही लिए है।

श्री राजीव शुक्ल: चुहिया पहाड़ से बड़ी हो गई हैं।

श्री सभापति: आपकी संगत में चुहिया रहेगी तो मोटी होगी हो।

श्री मती विजया चक्रवर्ती : सभापति जी, मैं जवाब देना चाहती हूं ....(**व्यवधान**)...

प्रो.राम देव भंडारी: मैंने सवाल नहीं पूछा है....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: राम देव जी, क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी के भी क्वेश्चन हैं।

प्रो.राम देव भंडारी: कमला नदी पर बांध बनाने की योजना थी, बागमती नदी पर भी बांध बनाने की योजना थी। उन योजनाओं के बारे में इन्होनें लिखा है कि विचार-विमर्श चल रहा है। सभापति जी, जब रोगी मर जाएगा तब डाक्टर क्या करेगा। बिहार की यह हालत है...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूं। इन दो नदियों के बारें में आपके क्या विचार है, बोलिए।

प्रो.राम देव भंडारी: सभापति महोदय, इनका विचार-विमर्श चल रहा है। कितने अरसे से यह विचार-विमर्श चल रहा है ? पचास वर्ष से हम लोग इस पर जोर डाल रहे हैं। बिहार के सभी सदसय, सिर्फ मेरी पार्टी ही नहीं...(**व्यवधान**)....

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

प्रो.राम देव भंडारी: दूसरी पार्टियों के भी सांसदों इस संबंध में चर्चा करते हैं। कृपा करके बताइए। बिहार की तकदीर इससे जुड़ी हुई है।

श्री सभापति: बोलिए।

श्री मती विजया चक्रवर्ती: सभापति जी, माननीय मैम्बर ने जो क्वेश्चन पूछा है, वह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं सदन और माननीय मैम्बर को यह बताना चाहती हूं कि जो प्रोजेक्ट 1947 से नेपाल के साथ शुरू हुआ था वह प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी के नेतृत्व में 2000 में बात आगे बढ़ी। 2001 में, आपने बताया था कि सप्तकोसी और सुनकोसी जिसकी इनसेप्शन रिपोर्ट बनी थी।आपने पूश्न पूछा है। जो छह नदियां नेपाल से होकर बिहार डायरेक्ट होकर आती है उनमें बागमती, कमला, कोसी और गंडक भी है। आपने बागमती और कमला के बारे में पूछा है।हम लोगों की नेपाल के साथ ज्वाइंट मीटिंग हुई थी लेकिन कुछ टेक्नीकल कारण से अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। नेपाल के साथ हमारी अभी भी पूरा समझौता नहीं हुआ है। नेपाल में हमारा ज्वाइंट रिलेशन ऑफिस बनेगा। विराट नगर में सप्तकोसी और सुनकोसी के लिए हमारा आफिस होगा लेकिन कमला और बागमती के लिए अभी कुछ दिन लगेगें। नेपाल ने यहां इन्वायरमेंट का इश्यू उठाया है।लोगों के डिसप्लसेमेंट की बात भी आई है,इसीलिए कुछ टेक्नीकल कारण से कमला ओर बागमती में थोड़ी-सी देर हुई हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि अभी नेपाल के ऑनरेबल किंग भारत में आ रहे हैं, इनके आने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से जब भी बात होगी उसी समय कमला और बागमती का जो प्रोजेक्ट बनना है, उस पर भी बात होगी।

श्री सभापति: आपके आश्वासन के आधार पर मैं माननीय सदस्य का आश्वासन दे दूं...(**व्यवधान**)....

प्रो.राम देव भंडारी: एक छोटा-सा सवाल है।

श्री सभापति: छोटा-सा ही कीजिए।

प्रो.राम देव भंडारी: सभापति जी, आप आश्वासन दे दीजिए।

श्री सभापति: मैं इनके आश्वासन के आधार देना चाहता हूं।अभी नेपाल के किंग आ रहे है उस समय इस मामले पर चर्चा होकर कोई न कोई निर्णय होगा।

प्रो.राम देव भंडारी: सभापति महोदय, धन्यवाद, मेरा एक और छोटा-सा सवाल है। जब तक नेपाल में डैम नहीं बन जाता है, बाढ़ तो आती रहेगी, नदियों पर इमबैन्कमेंट बना हुआ है, हर साल बिहार सरकार को बांध टूटने से करोड़ों रूपये का नुकसान होता है, बिहार सरकार ने पाचं सौ करोड़ रूपए की एक योजना भेजी है। उस योजना में बांधो के सुद्दढ़ीकरण और उच्चीकरण की बात है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर वर्ष यह होगा। सभापति जी, मैं भुक्तभोगी हूं। मेरे घर में बाढ़ का पानी जाता है इसलिए मैं बड़े दर्द के साथ, दुख के साथ कह रहा हूं कि जो पाचं सौ करोड़ रूपए की योजना बिहार सरकार ने इन्हें भेजी है, इन्होंने लिखा भी है कि केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि उस योजना को सरकार ने स्वीकार क्यों नहीं किया है ? बिहार सरकार आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है कि अपने पैसे से वह बांध सुद्दढ़ीकरण और उच्चीकरण कर सके। बिहार सरकार की जो योजना आई है उस उसे स्वीकार क्यों नहीं करते है ? पैसा क्यों नहीं देते है? सभापति जी, आप कृपा करके इस पर भी आश्वासन दिला दें तो आपकी बहुत कृपा होगी।

श्री सभापति: मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि बिहार की नदियों को आप राजस्थान ले जाएं। आपका भी स्वागत होगा और हमारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा।

प्रो.राम देव भंडारी: सभापति जी, हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आप राजस्थान से दिल्ली आ गए है और आप मुझे कहां राजस्थान भेज रहे हैं।

श्री मती विजया चक्रवर्ती: सभापति जी, आपकी तरफ से मैं माननीय मैम्बर को आश्वासन दे सकती हूं कि हम बिहार सरकार का विभिन्न हेडिंग पर काफी पैसा दे रहे है। फ्लड ग्रूफिंग के तहत हम लोग संकल्पित है थर्टी रेशों के हिसाब से। मतलब सेवेन्टी परसेंन्ट सैंट्रल गवर्नमेंट देगी और थर्टी परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस हिसाब से हम लोग 2.37 करोड़ रूपये दे चुके है। आपकी जानकारी के लिए और बात बताना चाहती हूं कि टेंथ फाइव ईयर प्लान के लिए जो प्रपोजल आना चाहिए, अभी तक बिहार सरकार से कोई प्रपोजल...(व्यवधान)...

प्रो.राम देव भंडारी: पांच सौ करोड़ का प्रपोजल आया है आपके पास...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप ऐसे मत खड़े होइए। बोलने से पैसे थोड़े ही मिलते हैं।

श्री मती विजया चक्रवर्ती: मैं पूरीजिम्मेदारी से यह बताती हूं कि अभी तक बिहार सरकार ने कोई प्रपोजल फ्लड प्रूफिंग प्रोग्राम के लिए नहीं दिया है। मेन्टेन्स के लिए ....(**व्यवधान**)....

प्रो.राम देव भंडारी: बांधों के सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण के लिए...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सुनिए, सुनिए...(**व्यवधान**)...

श्रीमतीविजया चक्रवर्ती: ...(**व्यवधान**)...सुनिए,सुनिए...(**व्यवधान**)...सेवन प्वाइन्ट फिफ्टी थी करोड़ ऑलरेडी दे चुके है। क्रिटीकल एंटी एरोजन वर्क में सेवेन्टी फाइव/ ट्वेन्थी फाइव बेसिस पर हम लोग 30.38 करोड़ ऑलरेडी दे चुके है। 31 मार्च तक हम लोगों ने आपको और चार करोड़ देने का वादा किया है।

श्री सभापति: बस,बस काफी हो गया है।

प्रो.राम देव भंडारी: महोदय, यह कोई सामान्य बात नहीं है, हर साल बाढ़ आती है ?

श्री सभापति: श्री.ए.आर.किदवई। एक्स गवर्नर बिहार बोल रहे हैं।

प्रो.राम देव भंडारी: धन्यवाद , महोदय।

DR. A. R. KIDWAI: Sir, the problem is really serious because from Varanasi up to Farraka, the entire area gets flooded for several months. This is because of the silting of Ganges and its tributaries. Therefore, the immediate requirement is that rivers, including the Ganges should be desilted so that spread of water is stopped. So, I would like to know as to what steps the Ministry is taking in this regard. The Ministry's approach is not correct. They are not taking any steps to desilt these rivers.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, in fact, the rivers originating from Nepal come from a very high land. When these rivers flow, they carry heavy silt. The hon. Member is very right in saying that this heavy silt creates a lot of problems. Here, in our Ministry, there is no such proposal to dig the river. It is with the Ministry of Shipping. If the river is dug up, it will help in irrigation also. So far as our work is concerned, we will, surely, take various measures in the Tenth Plan. We will surely discuss it with the Expert Committee so that appropriate measures may be taken to stop the silt coming to the main current of the flow of different rivers, the Ganges and its tributaries.

श्री सभापति : एल.एम.सिंघवी...(**व्यवधान**)....

प्रो,राम देव भंडारी: महोदय, महोदय...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं देखिए...(**व्यवधान**)...हिम्मत कीजिए...(**व्यवधान**)...आप बैठिए।

प्रो.राम देव भंडारी: सभापति जी, बिना डैम के सिल्ट नहीं रूकेगा।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: डैम में भर जाएगा ...(**व्यवधान**)....

प्रो.राम देव भंडारी: डैम बनाइए, बिना डैम के सिल्ट नहीं रूकेगा।

DR. LM. SINGHVI: Sir, though it is true that flood management is a State subject, I think the Government has to recognise that in the special circumstances of Bihar, it is a diplomatic challenge, and the Central Government must give it the highest priority. In view of your assurance, Sir, we would like to know from the Minister whether any groundwork is being laid in order to negotiate a quicker and lasting solution to this problem in our negotiations with Nepal, and not only to say that the project proposal is being approved by India but that everything else is being withheld by Nepal. We would like to know what are the specific and concrete time bound steps being taken for flood control through negotiations with Nepal.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, regarding the Sapta Kosi Dam Multipurpose Project and Sunkoshi Storage-cum-Diversion Scheme, already, a joint team of experts has been set up. Here, we have included the Engineer in Chief of Bihar Government as one of the Members and already it is on the job. For the detailed project report, already, an amount of Rs. 29 crores has been earmarked and this will be entirely spent by the Government of India. The component of the project will be Sapta Kosi High Dam; Re-regulating Dam at Chatra across Kosi; Sun Kosi Diversion Dam at Kurule; Diversion Dam/Barrage on the Kamala river; Diversion Tunnel about 16.5 Kms from Sun Kosi to Kamala Basin; Command area and Canal System, both in India and Nepal; Hydropower Generation at Kosi Chatra, Sun Kosi and Kamala Dam/Barrages. Moreover, there will be high facility for navigation also when the entire project will be completed. So far as these two projects are concerned, although it will be a single component on a single river, we have spread it as two projects. And it would be highly beneficial to check the erosion and to check the silt, as the hon. Member has referred to here, and to have a proper flood control measure in the

entire Bihar, including Madhubani, almost bordering Nepal.The problem of high-level flood, we hope, will be solved with the completion of these projects.

मध्य प्रदेश के शहरों को विमान सेवा से जोड़ा जाना

*283. **श्री पी.के.माहेश्वरी**: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि:

(क्) मध्य प्रदेश के कितने शहर नियमित या साप्ताहिक विमान सेवा से जुड़े है और प्रतिदिन तथा प्रति सप्ताह कितनी उड़ानें संचालित की जा रही हैं :,

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश से कितने लोगों ने इन उड़ानों से यात्रा की:,

(ग) क्या सरकार ने कुछ उड़ानें बंद कर दी है:, यदि हां, तो उसके क्या कारण है:,और

(घ) निजी विमान कम्पनियों तथा इंडियन एअरलाइंस द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कितना अंतर है और इसके क्या कारणहै ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) एलाइंस एयर और जेट एयरवेज मध्यमप्रदेश खजुराहो, भोपाल और इन्दौर से/के लिए निम्निलिखित विवरण के अनुसार हवाई सेवा प्रचालित कर रही है:-

एलाइंस एयर

दिल्ली-भोपाल,इन्दौर-मुम्बई और वापसी	दैनिक
दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणीस और वापसी	सप्ताह में एक बार
दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी-आगरा –दिल्ली	सप्ताह में दो बार

जेट एयरवेज

मुम्बई-इन्दौर-मुम्बई	सप्ताह में दो बार
मुम्बई-भोपाल-मुम्बई	दैनिक
दिल्ली-इन्दौर-दिल्ली	सप्ताह में 13 उड़ाने
दिल्ली-वाराणसी-खजुराहो और वापसी	दैनिक